



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216161
CG-DL-E-14022020-216161

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सं. 1/2020—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 117(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उन पर लगाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से उस स्थिति में छूट देती है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.95 और 4.96 के साथ पठित स्कीमफॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़ ऑन एक्स्पोर्ट्स ऑफ गार्मेंट्स एंड मेड-अप्स (एतश्मिन पश्चात जिसे आरओएससीटीएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी ज्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात उक्त स्क्रिप से संदर्भित किया गया) के एवज में क्लीयर किया गया हो।

बशर्ते कि उक्त स्क्रिप, जिसके एवज में उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से छूट प्रदान की गयी हो, में वह क्रेडिट भी आती है जो कि हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 4.95 और 4.96 के अनुसार अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अंतर्गत दिया गया हो।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-

- (1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हो;
- (2) कि ऐसी स्क्रिप का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह स्क्रिप मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतरित की गयी हो, उक्त स्क्रिप को उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफार्मा इनवॉइस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता द्वारा दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का ब्यौरा दिया गया हो और उस वस्तु का विवरण और मूल्य भी दर्शाया गया हो जिसे कि क्लियर किया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो;
- (3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, लागू होने वाले उस शुल्क को डेविट करेगा, यदि यह छूट न दी गयी हो तो या उक्त स्क्रिप को वापस किया गया हो तो और वह इससे संबंधित आवश्यक ब्यौरे का भी उल्लेख करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह भी देगा;
- (4) कि निकासी के समय स्क्रिप का धारक उक्त स्क्रिप को जिसको कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा डेविट किया गया हो, उक्त अधिकारी को सौंपेगा और साथ-ही-साथ एक ऐसी अंडरटेकिंग भी देगा जो कि उक्त अधिकारी को संबोधित हो और इस आशय का हो कि यदि उक्त स्क्रिप में कम राशि डेविट की गयी हो तो वह माफ किये जाने जितनी राशि का भुगतान करेगा जितनी राशि कम की गयी हो और साथ में ही वह उसपर लागू ब्याज का भुगतान करेगा;
- (5) कि उक्त लिखित सलाह और अंडरटेकिंग के आधार पर, उक्त अधिकारी निकासी के ब्यौरे को, उक्त स्क्रिप को वापस किये जाने पर, उसपर लगाये जाने वाले शुल्क के ब्यौरे, यदि यह छूट न दी गई हो तो, जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी ने डेविट किया हो, को अनुमोदित करता हो और ऐसे निकासी का रिकॉर्ड अपने पास रखता हो;
- (6) कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से विनिर्माता उक्त स्क्रिप की प्रति, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के द्वारा डेविट की गई हो और उक्त अधिकारी के द्वारा प्रष्ठांकित हो और स्क्रिप धारक के द्वारा विधिवत सत्यापित हो; और
- (7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल की निकासी की गई थी, उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के एवज में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में किसी भी बात के बावजूद 10 अप्रैल, 2019 को उसके बाद जारी की गई उक्त स्क्रिप के बारे में, जिसे पंजीकरण पत्तन पर बिना भौतिक प्रति के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया हो, जो कि सीमाशुल्क स्वचलन प्रणाली के तहत जारी किया गया हो, दी जाने वाली छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा:-

- (1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हो;
- (2) कि ऐसी स्क्रिप का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह स्क्रिप मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतरित की गयी हो, उक्त स्क्रिप को उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो

और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफार्मा इन्वोइस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता द्वारा दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का ब्यौरा दिया गया हो और उस वस्तु का विवरण और मूल्य भी दर्शाया गया हो जिसे कि क्लियर किया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो;

- (3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, यदि यह छूट न दी गयी हो तो सीमाशुल्क स्वचालन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस शुल्क को डेविट करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह देगा;
- (4) क्लियरेंस के समय उक्त स्क्रिप धारक उक्त अधिकारी को इस बात की अंडरटेकिंग सौंपेगा कि यदि उक्त स्क्रिप में कम राशि डेविट की गई हो तो वह मांग किये जाने पर उक्त कम राशि के बराबर, की राशि तथा उसपर लगने वाले ब्याज का भी भुगतान करेगा;
- (5) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्राप्त लिखित सलाह और उक्त अंडरटेकिंग के आधार पर उक्त अधिकारी क्लियरेंस के ब्यौरे और उसकी वैधता, जो कि उक्त लिखित सलाह में दी गयी हो, यदि छूट न दी गई हो तो उस पर लागू शुल्क के ब्यौरे, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के द्वारा डेविट की गई हो, को पृष्ठांकित करेगा और निकासी के रिकॉर्ड को अपने पास रखेगा।
- (6) उक्त अधिकारी स्क्रिप धारक और विनिर्माता को उक्त पृष्ठांकित लिखित सलाह की एक विधिवत सत्यापित प्रति प्रदान करेगा, जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से अपने पास रखेंगे।
- (7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल को क्लियर किया गया था, उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के एवज में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में-

- (I) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसे भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01/2015-2020, 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित है।
- (II) “परिधान” और “मेड-अप्स” से वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (वॉल्यूम II), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसके द्वारा स्कीम फॉर रीबेट ऑफ स्टेट एन्ड सेन्ट्रल टैक्सेस एन्ड लेवीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एन्ड मेड-अप्स को अधिसूचित किया गया था, में दिया गया हो।
- (III) क्षेत्रीय प्राधिकारी से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त किसी विदेश व्यापार महानिदेशक से है या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है जो कि प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा स्क्रिप भी आती है।

[फा. सं. 605/04/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्राँबैक)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2020

No. 1/2020 – Central Excise

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Fourth Schedule to the said Act, when cleared against a duty credit scrip (hereinafter referred to as the said scrip) issued by the Regional Authority under the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made-ups (hereinafter referred to as the said RoSCTL scheme) in accordance with paragraph 4.01 (c) read with paragraphs 4.95 and 4.96 of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Act:

Provided that the said scrip, against which goods specified in the Fourth Schedule to the said Act when cleared are exempted from the whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, may include duty credit provided under the Additional Ad Hoc Incentive in terms of paragraphs 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures.

2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the conditions (1) to (3) specified in paragraph 2 of the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority);

(2) that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the said scrip to the said Customs Authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the said Officer) and the description, quantity, value of the goods to be cleared and the duties leviable thereon, but for this exemption;

(3) that the said Customs Authority, after taking into account the debits already made towards imports under the aforesaid notification No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020, and this exemption, shall debit the duties leviable, but for this exemption in or on the reverse of the said scrip and shall mention the necessary details thereon, update its own records and send written advice of these actions to the said Officer;

(4) that at the time of clearance, the holder of the scrip presents the said scrip debited by the said Customs Authority to the said Officer along with an undertaking addressed to the said Officer that in case of any amount short debited in the said scrip, he shall pay on demand an amount equal to the short debit, along with applicable interest;

(5) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer endorses the clearance particulars and validates, on the reverse of the said scrip, the details of the duties leviable, but for this exemption, which were debited by the said Customs Authority, and keeps a record of such clearances;

(6) that the manufacturer retains a copy of the said scrip, debited by the said Customs Authority and endorsed by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the clearance under this notification; and

(7) that the said holder of the scrip, to whom the goods were cleared, shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the Fourth Schedule to the said Act, against the amount debited in the said scrip and validated at the time of clearance.

3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, in respect of the said scrip issued on or after the 10th April, 2019 electronically without a physical copy for a port of registration enabled on the customs automated system, the exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

- (1) that the conditions (1) to (3) specified in paragraph 2 of the notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13/2020-Customs, dated 14th February, 2020 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority);
- (2) that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents details of the said scrip to the said Customs Authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the said Officer) and the description, quantity, value of the goods to be cleared and the duties leviable thereon, but for this exemption;
- (3) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made towards imports under the aforesaid notification No. 13/2020-Customs, dated the 14th January, 2020, and this exemption, shall debit the duties leviable, but for this exemption electronically in the customs automated system and send written advice of these actions to the said Officer;
- (4) that at the time of clearance, the holder of the scrip submits an undertaking addressed to the said Officer that in case of any amount short debited in the said scrip he shall pay on demand an amount equal to the short debit, along with applicable interest;
- (5) that based on the said written advice received from the said Customs Authority and the said undertaking, the said Officer endorses the clearance particulars and validates, on the face of the said written advice, the details of the duties leviable, but for this exemption, which were debited by the said Customs Authority, and keeps a record of such clearances;
- (6) that the said Officer shall give a duly attested copies of the said endorsed written advice to the scrip holder and the manufacturer, who retains it in support of the clearance under this notification;
- (7) that the said holder of the scrip, to whom the goods were cleared, shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the Fourth Schedule to the said Act, against the amount debited in the said scrip and validated at the time of clearance.

Explanation. – For the purposes of this notification -

- (a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification number 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time;
- (b) "Garments and Made-ups" shall have the same meaning assigned to them in the Ministry of Textiles' notification No. 14/26/2016-IT (Vol. II), dated the 7th March, 2019 notifying the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made-ups.
- (c) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under that Act.

[F. No. 605/04/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)